

Government of Uttarakhand
Department of Excise
No: 112 / XXIII/09/39/2007
Dehradun: Dated: 05.02, 2009

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 40 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act No. IV of 1910), (As amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules further to amend the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) Rules, 2001.

The Uttarakhand Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Thirteenth Amendment) Rules, 2009.

- | | |
|--|--|
| 1. Short Title and Commencement | (1) These Rules may be called the Uttarakhand Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Thirteenth Amendment) Rules, 2008.
(2) They shall be deemed to come into force from 1 June, 2007. |
| 2. "Uttarakhand" to be read instead of "Uttaranchal" | In the Uttaranchal (Uttarakhand Excise Manual Volume - 1) (Adaptation and modification order, 2002) wherever the word "Uttaranchal" occurs, it shall be read as "Uttarakhand".
The following rule shall be inserted as Rule '3(c)' in the Rules :- |
| 3. Amendment of Rule 3(c). | "The retail sale rates of foreign liquor and beer shall be fixed by the Excise Commissioner as per the directions of the State Government". |
| 4. Amendment of Rule 7(c). | Rule '7(c)' of the Rules shall be substituted as :-

"Application for grant of licence shall be made on prescribed form, which shall be published in atleast two prestigious newspapers of the area and which could also be obtained from the office of the District Excise Officer. A processing fee, as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time, shall be deposited with the application form in cash or Bank Draft (Payable to the District Excise Officer) in the office of the District Excise Officer". |
| 5. Amendment of Rule 8(d) (iv) | The rule 8d (iv) shall be omitted . |
| 6. Amendment of Rule 8(e). | The following rule shall be substituted for Rule '8(e)':-

"He will furnish a bank draft drawn in favour of the Excise Commissioner or the District Excise Officer issued from a Scheduled bank or State and District Co-operative Banks / Urban Co-Operative Bank / Nationalized Banks Situated in Uttarakhand as earnest money. The amount of earnest money shall be 10 |



Percent of the licence fee or shall be fixed by the Excise Commissioner from time to time.

In case the applicant is selected as licensee, the earnest money shall be adjusted against the licence fee. In other cases it shall be returned as such to the applicant as soon as selection process is over.

Solvency Certificate and Character Certificate shall compulsorily be deposited with the application form. Application forms without Solvency Certificate and Character Certificate shall not be considered in any case and the licensing authority shall have full right to reject prima facie i.e. such application forms. If an applicant has no immovable property, he can mortgage the immovable property of his family with the licensing authority in order to get the Solvency Certificate. Licensee of a shop must compulsorily be a permanent resident of Uttarakhand hence **Permanent Resident Certificate** must also be attached with the application form at the time of allotment of the shop.

7. Amendment of Rule 10(c).

The 10 (c) of the Rules shall be substituted as follows:-

"Only one shop (either Country liquor or foreign liquor) shall be allotted to private individuals or Ex-Army Personnel in Uttarakhand. Application forms only from the Permanent residents of that Tehsil in which the shop is situated, shall be accepted".

8 Amendment of Rule 13.

Rule 13 of the Rules shall be substituted as follows :-

LIFTING OF LIQUOR :-

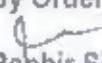
"The lifting of liquor against the minimum guaranteed duty shall be as per the Annual Policy Guidelines and Tax Structure issued by the Government from time to time".

9. Amendment of Rule 14.

Rule 14 of the Rules shall be substituted as follows :-

LIFTING OF MONTHLY MINIMUM GUARANTEED QUANTITY:-

"The lifting of Monthly Minimum Guaranteed Quantity shall be as per the Annual Policy Guidelines and Tax Structure issued by the Government from time to time".

By Order,

 (Dr. Ranbir Singh)
 Secretary

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी विभाग,
संख्या J/2 /XXIII /09 /39 /2007
देहरादून: 05 फरवरी, 2009

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 (अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (समय-समय पर यथासंशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल आबकारी (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2009

1. राक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2009 कही जायेगी।

(2) यह 1 जून 2007 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. 'उत्तरांचल' के स्थान पर 'उत्तराखण्ड' पढ़ा जाय।

उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में जहाँ-जहाँ शब्द 'उत्तरांचल' आया है, यहाँ-यहाँ वह शब्द 'उत्तराखण्ड' पढ़ा जायेगा।

3. नियम 3 (ग) का संशोधन.

नियमावली में नियम 3 (ग) निम्नानुसार जोड़ दिया जायेगा :-

विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री मूल्य का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4. नियम 7 (ग) का संशोधन.

नियमावली के नियम 7 (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा:-

“लाइसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेगा जिसे, सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा एवं जिसे जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग फीस, जिसे समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तय किया जायेगा, नकद अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी”।

5. नियम 8 (ब)
(चार) का संशोधन

नियमावली का नियम 8 (घ) (चार) हटा दिया जायेगा :-

6. नियम 8 (ड.) का
संशोधन

नियमावली का नियम 8 (ड.) निम्नानुसार प्रतिपास्थित किया जायेगा :-

यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित, राज्य एवं जिला सहकारी बैंक, अरबन को-ऑपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करेगा। धरोहर धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की सहमति से समय-समय पर निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि को अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा। अन्य मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ शोध क्षमता (सॉल्वेंसी) प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ शोध क्षमता (सॉल्वेंसी) प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न न होने की दशा में ऐसे आवेदनों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवेदनों को प्रथम दृष्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अनुज्ञापन (लाइसेन्सिंग) प्राधिकारी को होगा। यदि किसी आवेदक के नाम अचल सम्पत्ति नहीं है तो वह अपने परिवार की सम्पत्ति को शोध क्षमता (सॉल्वेंसी) प्रमाण-पत्र के रूप में अनुज्ञापन (लाइसेन्स) प्राधिकारी के नाम बन्धक कर शोध क्षमता (सॉल्वेंसी) प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है। अनुज्ञापी का स्थायी रूप से उत्तराखण्ड का निवासी होना अनिवार्य है, दुकान हेतु आवंटन करते समय आवेदन पत्र के साथ स्थायी निवास प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।

7. नियम 10 (सी)
का संशोधन

नियमावली का नियम 10 (सी) निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा

निजी व्यक्तियों अथवा भूतपूर्व सैनिकों को पूरे राज्य में देशी अथवा विदेशी मदिरा की केवल एक दुकान आवंटित की जायेगी। दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो, उसी तहसील के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे।

8. नियम 13 का
संशोधन

नियमावली के नियम 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा :-

मदिरा का उतान :-

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत वार्षिक नीति एवं टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार मदिरा के उतान पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर देय होगा।

9. नियम 14 का संशोधन।

नियमावली के नियम 14 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा :-

मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान :-

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत वार्षिक नीति एवं टैक्स स्टक्चर के अनुसार मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान किया जायेगा।

आज्ञा से,

डॉ० रणवीर सिंह
सचिव

संख्या: 12(i)/XXIII /09 /39 /2007 तददिनांकित।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, जनपद-हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 (क) के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा इसकी 100 प्रतियाँ सचिव, आवकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4- सुभाष रोड, देहरादून को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

बी०आर० टम्टा
अपर सचिव।

संख्या: 12(ii)/XXIII /09 /39 /2007 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, विधायी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आवकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. निदेशक, एग० आई० सी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

11/05/09
(बी०आर० टम्टा)
अपर सचिव।